हिन्दी दैनिक

R.N.I.NO.UPHIN/2014/59804

प्रयाग दर्पण

वर्ष : 08 | अंक : 132 | प्रयागराज, शनिवार 20 अगस्त , 2022 | हिन्दी दैनिक | पृष्ठ–4 | मूल्य : 2 रुपया

सीएम योगी ने बलिया को दी मेडिकल कॉलेज व स्मारक की सौगात, एयरपोर्ट जैसा बनेगा बलिया का बस स्टेशन

बलिया। यूपी के बलिया के ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के लिए दो बड़ी सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और जिला कारागार को बाहरी हिस्से में शिफ्ट कर वर्तमान जिला जेल को सेनानियों का स्मारक बनाने की घोषणा की। शुक्रवार को बलिया पुलिस लाइन में आयोजित बलिया बलिदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांच साल से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मांग रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही थी। तीन साल पहले ही यह काम हो जाना चाहिए था। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुख्य सचिव यहीं बलिया में पढ़े–बढ़े हैं। आज इसी काम के लिए उन्हें साथ लेकर आया हूं। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर जाऊंगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व व बलिया बलिदान दिवस के सुखद संयोग पर बलिया आगमन को खुद का सौभाग्य बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि बलिया का अपना इतिहास रहा है। यह ऋषियों, मुनियों व क्रांतिकारियों की भूमि है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से बलिया को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया की धरती के लाल अमर सेनानी मंगल पांडेय ने आजादी की लड़ाई की जो चिंगारी बैरकपुर छावनी (मेरठ) में जलाई, वह पूरे देश के लिए प्रेरक बनी। 1942 में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था तब महान क्रांतिकारी चित्तू पांडेय की अगुवाई में बलिया ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 50 हजार की संख्या में बलिया के लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को तमाम क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करना पड़ा। चित्तू पांडे जिलाधिकारी और महानंद मिश्र पुलिस अधीक्षक की भूमिका में आए। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था लेकिन बलिया ने कभी बलिदान से संकोच नहीं किया। बलिया बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया की माटी के लाल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई लोकनायक जयप्रकाश जी ने शुरू की थी उसमें चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। योगी ने कहा कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आगे बढ़ाया था। अब इसे एक वर्ष और बढ़ाया गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने सबको पांच संकल्प दिलाए हैं। इन संकल्पों के अनुरूप भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना ही हम सब का संकल्प होना चाहिए। आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सभी को पीएम मोदी के बताएं पांच संकल्पों को साथ लेकर चलना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी गुलामी की निशानी ना रहे। यदि हम सभी अपने अपने क्षेत्र के कार्य का इमानदारीपूर्वक निर्वहन करें तो कोई भी ताकत हमें इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाने से रोक नहीं सकती।

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर सीएम योगी ने की गौसेवा, प्यार दुलार कर खिलाया गुड़

गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ सूबे का मुखिया होने के साथ–साथ गौसेवा करने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। वह लखनऊ हो या गोरखपुर में हो उनका गौ–प्रेम दिखता रहता है। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर गोशाला में आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने गायों को प्यार दुलार करने के बाद गुड़ और रोटी खिलाई।

शुक्रवार की सुबह दिनचर्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ जी के दर्शन कर पूजन किया। उसके बाद अखंड ज्योति के दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर पहुंचे। उन्होंने वहां माथा टेका, उसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया। गोशाला में काम काज देखने वाले सेवादारों को जरूरी हिदायत दी। सीएम योगी सुबह करीब नौ बजे हेलीकॉप्टर से बलिया के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह 11.15 बजे बलिया से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।

दिल्ली आबकारी नीति मामला, सिसोदिया के आवास सहित 21 स्थानों पर सीबीआई के छापे

नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 19 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई के दल 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 21 स्थानों पर पहुंचे, जिसमें सिसोदिया और एजीएमयूटी काडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी एवं पूर्व आबकारी आयुक्त गोपी कृष्ण के परिसर भी शामिल हैं। दो अन्य लोक सेवकों के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021–22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)–1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम–2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम–2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट में पाया गया कि निविदा जारी करने के बाद ''शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ''जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक की गई। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। इस बीच, सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि वह सीबीआई का स्वागत करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर–एक नहीं बन पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी वैश्विक स्तर पर सराहे जा रहे उनके अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है।

राजस्थान: बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी 20 अगस्त को जयपुर में करेगी विरोध प्रदर्शन

जयपुर। अपराध और अराजकता की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर भाजपा 20 अगस्त को महिलाओं और संतों पर अत्याचार, अवैध खनन, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं पर हमले और अन्य मुद्दों के खिलाफ जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन साल में किसी पूर्णकालिक गृह मंत्री की नियुक्ति नहीं की।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में राज्य के गृह विभाग के प्रभारी हैं। पूनिया ने आगे बताया, अगर मुख्यमंत्री राज्य में कुछ सुधार लाते तो कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन हालात देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों के बाहर एक टैगलाइन लिखी है, जो कहती है, आम आदमी पर भरोसा–अपराधियों में डर, लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान, यह दूसरा तरीका है जो अपराधियों पर भरोसा और आम लोगों के बीच डर है। पिछले साढ़े तीन साल में राजस्थान में सात लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 6,325 हत्या के मामले आ चुके हैं। लूट के 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि चोरी की घटनाएं एक लाख से अधिक हो गई हैं और महिलाओं पर अत्याचार के लगभग 1.45 लाख मामले सामने आए हैं। कम से कम 22,000 मामले बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित थे जबकि 26,000 से अधिक मामले अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से संबंधित थे। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, बलात्कार, चोरी आदि में वशद्धि हुई है। चोरी के मामलों में 21.53 प्रतिशत, डकैती में 28.57 प्रतिशत, बलात्कार में 19.34 प्रतिशत, महिलाओं पर अत्याचार के 18.75 प्रतिशत मामलों की वशद्धि हुई है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कानून–व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार के दौरान एससी और एसटी समुदायों के लोगों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया गया है।

बिजनौर: चलते ट्रक में लगी भीषण आग

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगते ही सड़क पर अफरा–तफरी मच गई। आनन– फानन में ट्रक ड्राइवर ने कूद कर मौके पर अपनी जान को बचाई। लोगों ने मामले की जानकारी फायर बिग्रेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक मामला बिजनौर जिले के थाना हीमपुर दीपा के अकबरपुर तिगरी का बताया जा रहा है। जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते जब तक आग ने भीषण रूप ले लिया। मामले की जानकारी फायर बिग्रेड को दी गई। सूचना पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। समय रहते ही ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच कर मौके पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कि आग कैसी लगी है।

अध्यक्ष पद के लिए 'राहुल की हां और ना' को लेकर कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही पार्टी के भीतर इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है कि अगर राहुल गांधी फिर से कमान संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर विकल्प क्या होगा ? पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के भीतर इन विकल्पों को लेकर मंथन चल रहा है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो गांधी परिवार के किसी विश्वासपात्र नेता को कमान सौंपी जाए या फिर सोनिया गांधी ही अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालती रहें।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से आरंभ होनी है और इसे 20 सितंबर तक पूरा होना है। उधर, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, ''मतदान के लिए डेलीगेट की सूची तैयार है। हमारी ओर से हम तैयार हैं। कांग्रेस कार्य समिति को चुनाव की तिथि तय करनी है।'' पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की राय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस पर 'हां' का इंतजार है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, ''इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही भावना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि खुद वह तैयार हों। मेरी जानकारी के हिसाब से फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार हैं।'' उन्होंने कहा, ''2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, उसके बाद से कई मौकों पर पार्टी के नेता उनसे फिर से अध्यक्ष बनने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से 'हां' में जवाब नहीं आया। अब अध्यक्ष के चुनाव की दिशा उनकी 'हां और ना' पर निर्भर करती है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''अगर गांधी परिवार से इतर भी कोई अध्यक्ष बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राहुल गांधी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बने रहेंगे।'उनका यह भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पूरी स्थिति साफ हो सकती है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर समाधान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ''समानता, न्याय और आपसी सम्मान'' के सिद्धांतों और कश्मीर मुद्दे के समाधान के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा व्यक्त की है। मीडिया की एक खबर में शुक्रवार को यह कहा गया। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार से आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ''सहायक भूमिका'' निभाने का भी आग्रह किया। डॉन' अखबार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हवाले से बताया कि शरीफ ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त उच्चायुक्त नील हॉकिन्स के साथ बैठक के दौरान ये विचार व्यक्त किए।

शरीफ ने कहा, ''पाकिस्तान समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इस संदर्भ में, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद का एक उचित और शांतिपूर्ण समाधान अपरिहार्य है।'' उन्होंने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संबंध में एक सहायक भूमिका निभानी होगी, क्योंकि यह दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।'' भारत ने पाकिस्तान से बार–बार कहा है कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा के बाद द्विपक्षीय संबंध और बिगड़ गए। भारत ने पाकिस्तान से बार–बार कहा है कि जम्मू कश्मीर ''हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा बना रहेगा।'' भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने की भी नसीहत दी है।

सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस दिए जाएं : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालयों को सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस देना जरूरी है ताकि उन्हें अपने बचाव का मौका मिल सके। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हत्या के एक मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। पीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि राज्य ने अपीलकर्ताओं को मौत की सजा नहीं देने के सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती नहीं दी। पीठ ने कहा, ''निस्संदेह उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था और सजा को बढ़ा सकता था। हालांकि, ऐसा करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को नोटिस देना आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।'पीठ ने कहा, ''उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिए बिना उनकी सजा को बढ़ा दिया गयाकृ।''शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे दो आरोपियों द्वारा दायर किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में आता है।

निचली अदालत का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सुनवाई लंबी न खिंचे : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गवाहों से जिरह में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना निचली अदालत का कर्तव्य है कि सुनवाई लंबी न हो, क्योंकि लंबा अंतराल होने पर गवाही में समस्या पैदा होती है। न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि निचली अदालत को सुनवाई में देरी की किसी भी रणनीति को नियंत्रित करना चाहिए। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक मेयर के हत्यारों को भागने में मदद करने के एक आरोपी को जमानत देते समय यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि वह व्यक्ति पिछले सात साल से जेल में है और अभियोजन पक्ष के गवाहों से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। पीठ ने कहा, ''हम इस तथ्य से परेशान हैं कि घटना के सात साल बाद भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये हैं और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। समय का (लंबा) अंतराल गवाही में खुद ही समस्याएं पैदा करता हैकृ।' पीठ ने कहा, ''यह सुनिश्चित करना अभियोजन का कर्तव्य है कि अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों और यह सुनिश्चित करना निचली अदालत का कर्तव्य है कि किसी भी पक्ष को मुकदमे को आगे खींचने की अनुमति न दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर मौजूदा मामले का फैसला उपलब्ध हो।

सम्पादकीय

जब बलिया हुआ आजाद

एक दो लाल पगड़ी फेंक दो, एक दो तीन, लाल पगड़ी छीन, एक दो तीन चारध् लाल पगड़ी फाड़ डाल। बचपन में अलाव तापते हुए इन नारों को जब पहली बार सुना था, तो मन रोमांच से भर गया था। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' प्रस्ताव के पारित होने के बाद बलिया में आजादी की जो चिंगारी जगी, उसने देश के इतिहास में एक नया तराना लिख दिया। लाल पगड़ी तब अंग्रेज सरकार के पुलिस के सिपाहियों की पहचान हुआ करती थी। यह नारा भी तब यूं ही नहीं गढ़ा गया था। नौ अगस्त, 1942 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चोटी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो दावानल भारतीय दिलों में उबल पड़ा था, उसकी तपिश बलिया तक अगले ही दिन पहुंच गयी थी।

सुराजी लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन यह आंदोलन निर्णायक तब हुआ, जब 18 अगस्त को बलिया के पूर्वी छोर पर स्थित बैरिया थाने पर पास के बाबा लक्ष्मण दास हाइस्कूल और मिडिल स्कूल के छात्रों ने तिरंगा फहराने की सोची। नारायण गढ़ निवासी कौशल कुमार सिंह की अगुआई में छात्रों का दल तिरंगा फहराने चला, तो पहले थानेदार ने अनुमति दे दी, लेकिन उसके मन में अंग्रेजी दासता का कीड़ा छुपा हुआ था और उसने छात्रों पर गोलियां बरसा दीं। इस घटना में कौशल कुमार सिंह और पदुमदेव पांडे समेत 19 छात्र शहीद हुए। अपने नौनिहालों की इस नृशंस हत्या से पूरा इलाका विचलित हो उठा। लोग थाने की तरफ बढ़ चले। उन्मादी भीड़ देख बैरिया थाने के पुलिस कर्मियों के हाथ–पांव फूल गये और वे भाग खड़े हुए। भीड़ ने रास्ते में पड़ने वाले थानों पर भी हमला किया और वहां तिरंगा फहरा दिया। देखते ही देखते यह क्रांति इतनी तेज हो गयी कि पूरे जिले से अंग्रेज अफसरों को भागना पड़ा। बलिया में नौ अगस्त, 1942 को ही राधा मोहन सिंह, परमात्मा नंद सिंह और रामनरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। चित्तू पांडेय, राजेश्वर तिवारी, शिवपूजन सिंह, महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे, ठाकुर जगन्नाथ सिंह, तारकेश्वर पांडेय, युसूफ कुरैशी भी हिरासत में थे। छात्र नेता तारकेश्वर पांडेय के नेतृत्व में पूरे बलिया में इन गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और हड़ताल रखी गयी। शहर में विश्वनाथ मर्दाना के नेतृत्व में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला। सभा को संबोधित करने वाले रामअनंत पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्थरारोड में पारसनाथ मिश्र के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन हुए। आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। जानकी देवी, कल्याणी देवी और पार्वती देवी के नाम अविस्मरणीय हैं। जनपद के विभिन्न स्थानों पर जनता के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। इस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्रों की एक टोली रेल से चली और रास्ते में पड़ने वाले थानों को लूटती गयी। डाकखानों को भी लूटा गया।

क्या भारत की न्यायपालिका के अंदर विचारधारात्मक खिसकाव है?

वह 1990 के दशक का उत्तरार्द्ध जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अदालत के चौम्बर के शुद्धिकरण का मामला सुर्खियों में था। दरअसल उपरोक्त चेम्बर पहले अनुसूचित जाति से सम्बद्ध न्यायाधीश के लिए आबंटित हुआ था और उनके तबादले के बाद किन्हीं उच्च जाति के व्यक्ति को उस चेम्बर का आबंटन हुआ। खबर यह बनी कि श्उच्च जातिश के उपरोक्त न्यायाधीश ने श्गंगाजलश से उसका शुद्धिकरण करवाया। अखबार के रिपोर्टरों ने उन सम्बद्ध व्यक्तियों से भी बात की थी, जो इस कार्रवाई में शामिल थे। खबरों को पढ़ कर अनुसूचित जाति से सम्बद्ध न्यायाधीश ने अदालत की शरण ली और उनके बाद वहां विराजमान हुए उच्च जाति के न्यायाधीश को दंडित करने की मांग की। मामला अंततः अदालत द्वारा ही रफा दफा किया गया, बाद में पता चला कि अदालत ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसने उन लोगों से बात तक नहीं की थी, जो शुद्धिकरण में शामिल थे। अब बीते लगभग ढाई दशक में गंगा–यमुना से तमाम पानी बह चुका है, अलबत्ता ऐसी घटनाओं का कत्तई अकाल नहीं सामने आया है, जब न्यायाधीशों के जेण्डर, जातीय या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह सामने आए हैं और फिर यह सवाल भी उठता रहा है कि ऐसी मान्यताओं के आधार पर अगर वह न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तो वह जो फैसला लेंगे वह किस हद तक संविधान सम्मत होगा।

बहरहाल, पिछले दिनों यह बहस नए सिरे से उपस्थित हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने फिक्की

द्वारा आयोजित एक समारोह में विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में महिलाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में बात करते हुए स्त्रियों के सम्मान, उनकी मौजूदा स्थिति और धार्मिक ग्रंथों की अहमियत पर न केवल बात की बल्कि उनकी एक नयी परिभाषा भी देने की कोशिश की। गौरतलब था कि अपनी इस तकरीर में उन्होंने मनुस्मशति के कसीदे पढ़े। जज महोदया के इन विचारों की काफी आलोचना हुई। लोगों को इस बात पर भी ताज्जुब हुआ कि मनुस्मशति का उनका महिमामंडन न केवल उसके तमाम विवादास्पद पहलुओं की भी अनदेखी कर रहा था बल्कि भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक आजादी के आंदोलन के एक अहम पड़ाव के प्रति अपनी समूची अनभिज्ञता को प्रतिबिम्बित कर रहा था। याद रहे आजादी के आंदोलन में धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों एवं दलितों एवं अन्य वंचितों की स्थिति को लेकर विभिन्न सामाजिक क्रांतिकारक एवं सुधारकों ने लगातार अपनी आवाज बुलंद की है, यहां तक वर्ष 1927 में डॉ। अम्बेडकर की अगुआई में छेड़े गए महाड सत्याग्रह (1927) के दूसरे चरण में (25 दिसम्बर 1927) में महाड में डॉ। अम्बेडकर ने मनुस्मशति का दहन किया था और उनके इस कार्रवाई की तुलना फ्रेंच इन्कलाब (1789) से की थी, जबकि पहले चरण में (19–20 मार्च) को महाड के चवदार तालाब पर अपने हजारों सहयोगियों के साथ पानी पीकर मनुष्य होने के अपने अधिकार को रेखांकित किया था। गौरतलब था कि महाड सत्याग्रह की इस ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद समय–समय पर अपने लेखन और व्याख्यानों में डॉ। अम्बेडकर ने मनु के विष्व नजरिये की लगातार मुखालिफत की थी। महाड सत्याग्रह के लगभग 23 साल बाद जब भारत के संविधान का ऐलान हो रहा था तब डॉ। अम्बेडकर ने इस अवसर पर कहा था कि संविधान ने ष्मनु के षासन को समाप्त किया है। विडम्बना कही जाएगी कि इक्कीसवीं सदी की तीसरी दहाई में एक न्यायविद द्वारा मनुस्मृति का यह समर्थन– जिसे डॉ। अम्बेडकर ने ष्प्रतिक्रांतिष् का दस्तावेज कहा था– निष्चित ही कोई अपवाद नहीं कहा जा सकता। विगत कुछ वर्शों में ऐसे मामले बार–बार आए हैं, जब परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ न्यायविदों ने अपने ऐसे तमाम पूर्वाग्रहों को प्रकट किया है। दिसम्बर माह में जम्मू–कष्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष ने अधिवक्ता परिशद के कार्यक्रम में कहा था कि भारत के संविधान के प्राक्कथन में ष्धर्मनिरपेक्षष् और ष्समाजवादीष् षब्द के समावेष ने भारत की आध्यात्मिक छवि को सीमित किया है। इसके बाद जनवरी की षुरूआत में सुप्रीम कोर्ट के एक अग्रणी जज सुर्खियों में आए, जब उन्होंने इसी अधिवक्ता परिशद के सम्मेलन में षामिल होकर ष्भारतीय कानूनी व्यवस्था के गैरऔपनिवेषीकरणष् विशय पर बात रखते हुए यह दावा किया कि भारत की कानूनी प्रणाली एक तरह से औपनिवेषिक कानूनी प्रणाली की विरासत है, जो भारतीय जनताके लिए अनुकूल नहीं है तथा उसके भारतीयकरण की आवष्यकता है।उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत की कानूनी प्रणाली की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ओर लौटना होगा और हम पाएंगे कि भारत की वह न्याय प्रणाली कानून के राज पर टिकी थी।।।।उन्होंने इस बात पर भी अफसोस प्रकट किया कि किस तरह भारत की आधुनिक कानूनी प्रणाली ने मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, याज्ञवल्क्य आदि प्राचीन भारत के महान कानूनविदों के योगदानों की अनदेखी की है और वह औपनिवेषिक कानूनी प्रणाली चिपकी रही है। लाजिम था कि प्रबुद्ध दायरों में यह बहस चल पड़ी कि क्या न्यायपालिका के अंदर कोई गंभीर विचारधारात्मक षिफ्ट हो रहा है। याद कर सकते हैं कि बमुष्किल तीन साल पहले केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीष चिदंबरेष सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने ष्लोबल ब्राहमन मीटष् अर्थात वैष्विक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्राह्मण जाति की कथित वरीयता को रेखांकित किया था और सम्मेलन को यह आह्वान किया था कि आरक्षण का आधार क्या जाति होना चाहिए। न्यायमूर्ति के पूर्वाग्रह किस तरह समाज में व्याप्त विशाक्तता को मजबूती देते हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए अंत में हम मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले पर बात कर सकते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम युवक की लिंचिग के मामले में सभी अभियुक्तों को पैरोल पर रिहा किया। अदालत का तर्क था कि ष्यह मृतक की एकमात्र गलती थी कि वह दूसरे धर्म से सम्बद्ध था, यह तथ्य मैं अभियुक्तों के पक्ष में मानती हूं ।।। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर वह भड़क गए। अंत में सर्वोच्च न्यायालय को इस मुददे पर हस्तक्षेप करना पड़ा और अभियुक्तों की जमानत रद्द करनी पड़ी। कई उदाहरण, एक ही चिन्ता, भारत को पुराना गौरव कब हासिल होगा और हम विष्व गुरु कैसे बनेंगे? कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलवक्त इतना ही कहना काफी होगा कि आजादी की इस पचहत्तरवीं सालगिरह पर न्यायपालिका पर भी गहराते बादलों को हम देख सकते हैं, जो यह संकेत जरूर देते हैं कि चीजें अब जबरदस्त उथलपुथल में हैं। इसका समाधान क्या निकलेगा, इसका उत्तर भविश्य के गर्भ में है। **&सुभाष गाताडे**

आज का राशिफल

मेष :– कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता हेतु नये उत्साह का संचार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधा मधुरत होंगे।

वृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकार लोगों से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राओं का योग है।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली होगी।

कर्क :– भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का सही ढ़ंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन असंतुष्ट रहेगा। जरूरी कायरे में आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्य के प्रति भी ध्यान दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– परिवार की छोटी–छोटी बातों बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

तुला :– समय के साथ समझौता करके चलने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझें और स्वयं को उसी ओर केंद्रित करें। पत्नी के साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

वृश्चिक :– स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे।

धनु :– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्मित्ता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिले–जुले संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

मीन :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुिष्ट पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर ही रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है।

बलात्कारियों का सम्मान कर कैसा समाज बना रहे हैं हम?

फर्ज कीजिये किसी दिन आपको यह खबर मिलती है कि निर्भया के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है क्योंकि आजादी के मौके पर सरकार ने अच्छी चाल–चलन वाले और बीमार कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? निर्भया, जिसके साथ छह लोगों (जिनमें एक नाबालिग) ने बलात्कार किया था, अमानुषिक तरीके से मार–पीटकर घायल किया था और जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। यानी बलात्कार के बाद हत्या। आप कहेंगे कि उसके चार अपराधियों को तो फांसी हो गई, पांचवे ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी और एक माइनर को रिहा कर दिया गया। बेशक, सामूहिक बलात्कारी ऐसी ही सजा के लायक हैं। पूरा देश उस वक्त निर्भया के लिए उद्वेलित था जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए फिजिओथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। निर्भया की मां और पिता का सतत संघर्ष था जो अपराधी फांसी के फंदे तक पहुंचे। दूसरी तरफ बिलकिस बानो हैं जो लगभग निर्भया की ही उम्र की थीं जब मार्च 2002 के गुजरात दंगों में उनसे सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी तीन साल की बेटी मार दी गई, उनके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई, परिवार के सात सदस्यों को भी मार दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने मुजरिमों को सजा दी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। ये संख्या में 11 थे जिन्हें पंद्रह अगस्त को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। बेशक माफी का प्रावधान होता है लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में नहीं। यह ब्यौरा कई सवाल खड़े करता है। निर्भया के अपराधियों को फांसी, तो बिलकिस के बलात्कारियों को रिहाई क्यों? मामला जब सीबीआई का था तो राज्य सरकार माफी क्यों दे रही है? आरोपी पहले तिहाड़ जेल में थे, तो गुजरात की जेल में स्थानांतरित क्योंकर किये गए? गुजरात के विधानसभा चुनाव सामने हैं। क्या सरकार को इस बात का कोई डर नहीं कि इस रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा? बिलकिस बानो जैसों को न्याय अब मजहब को देखते हुए मिलेगा? जकिया जाफरी, तीस्ता सीतलवाड़ को जेल और अब बिलकिस बानो के अपराधियों की रिहाई न्याय की किस किताब

का प्रतिनिधित्व करती हैं? सर्वोच्च न्यायालय पहले भी बिलकिस बानो के हक में खड़ा हुआ था। क्या अब भी होगा? यह सब तब होता है जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान को लौटाने की बात करते हैं। कथनी और करनी के इस फर्क को क्या जनता इन दिनों नजरअंदाज कर रही है? शायद हां, तभी किसी राजनीतिक दल की सरकार ऐसी दरिंदगी करने वालों को माफी के काबिल समझने लगती है। फिर विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में उनके मस्तक पर तिलक लगते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। इसके वायरल हो रहे वीडियो पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश भी देंगे कि हमने जो किया उसके बाद हमें रिहाई भी दिलाई जाती है और सम्मान भी। पार्टी अकेला नहीं छोड़ती। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग के बाद ग्यारह अपराधियों के जेल से रिहा होते ही उनका फूलों की माला से स्वागत किया था। पीड़ित का नाम बिलकिस बानो हो जाने से क्या नजरिये में फर्क आ जाता है? निस्संदेह पार्टी को यह यकीन तो होगा ही कि इस फैसले से उनके मतदाताओं में उनकी पैठ नहीं घटने वाली। वास्तविक चिंता वोट बैंक की होनी चाहिए या उस सरोकार की जिससे देश की आधी आबादी भी सुरक्षित रहे। उन्नाव, हाथरस की घटनाओं से बहुत पहले राजस्थान के भटेरी गांव की भंवरी देवी भी हैं जिन्हें कोई न्याय नहीं मिला। भंवरी देवी के साथ तीस साल पहले सामूहिक बलात्कार हुआ था। वे साथिन (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) की ड्यूटी संभाल रही थीं और उन्होंने एक बाल विवाह को रुकवाया था। भंवरी देवी का बाल विवाह रुकवाना कथित ऊंची जाति वालों को बरदाश्त नहीं हुआ। भंवरी देवी का हुक्का–पानी बंद कर दिया गया और इस पर भी शांति न मिली तो पांच लोगों ने उसके पति के सामने उसका बलात्कार किया। 22 सितंबर, 1992 के बाद से भंवरी देवी मन्ने न्याय चाहिए की पुकार लगा रही हैं और तब से ही उनकी पुकार पर प्रहार का सिलसिला जारी है। घटना के 52 घंटे बाद तक उनका मेडिकल मुआयना नहीं किया गया। वे अपने पेटीकोट को ले लेकर भटकती रहीं। फिर कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि कोई ऊंची जाति वाला नीची जाति से बलात्कार कैसे कर सकता है? उन पर दबाव बनाया गया कि मुकदमा वापस ले लें लेकिन उनका कहना था कि अगर ये मेरा मान लौटा सकते हैं तो मैं भी मुकदमा वापस ले लूंगी। यही बात उन्होंने गांव के बुर्जुगों से भी कही। इस बीच खूब राजनीतिक दांव–पेंच खेले गए। सियासत बलात्कारियों की कवच बन गई। भंवरी देवी के कई रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। सिवाय उनके पति के। व्यवस्था जब यूं डोल रही हो तब स्त्री का भरोसा इस व्यवस्था में कैसे कायम रह सकता है? उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ चार ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया। पंद्रह दिन बाद दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जबरदस्ती गुपचुप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। व्यवस्था जब–तब एक स्त्री के सम्मान को यूं आग में भस्म करती रही है।– **वर्षा भम्भाणी मिजा**

खाद्यान्न उत्पादन की चुनौतियां

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2021–22 के लिए कृषि उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस अवधि में कुल उत्पादन 315।72 मिलियन टन हो सकता है। यह आकलन 2020–21 की तुलना में 4।98 मिलियन टन अधिक है। यदि पांच वर्षों के औसत उत्पादन के हिसाब से देखा जाए, तो यह अनुमान 25 मिलियन टन अधिक है। यह चौथा अग्रिम आकलन है, जिसके बाद वास्तविक आंकड़े जारी होंगे। आकलनों में बदलाव की गुंजाइश रहती है। इस आकलन में पिछले अनुमान की तुलना में गेहूं के उत्पादन में मामूली बढ़त दिखायी गयी है। पहले अनुमान लगाया गया था कि 106।4 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, जबकि इस चौथे अनुमान में यह आंकड़ा 106।8 मिलियन टन का है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान इससे कम हैं, क्योंकि अगर उत्पादन ठीक होता, तो बाजार में गेहूं की उपलब्धता होती। सरकार द्वारा होने वाली गेहूं की खरीद चौदह वर्षों में सबसे कम रही है। मई में सरकार को गेहूं निर्यात रोकने का निर्णय भी लेना पड़ा। केंद्र के पास जो गेहूं भंडार है, वह भी कई वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। ऐसे में इन आंकड़ों को, खासकर गेहूं के मामले में, ठीक से देखा जाना चाहिए। अगर आप बाजार को देखें, तो गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। कमजोर मानसून के कारण कृषि उत्पादन को लेकर नयी चिंताएं भी पैदा हुई हैं। देश में इस साल खरीफ की बुआई कम हुई है, सो चावल का उत्पादन गिरना तय है। हालिया

आंकड़ों के अनुसार धान का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में 43।83 लाख हेक्टेयर कम चल रहा है। पिछले साल 12 अगस्त तक धान की खेती का कुल क्षेत्रफल 353।62 लाख हेक्टेयर रहा था।

यदि आगामी दिनों में उत्पादन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो देश में 2।71 टन प्रति हेक्टेयर की चावल उत्पादकता के आधार पर चालू खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन करीब 110 लाख टन कम रह सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पूल में एक अगस्त को चावल और गेहूं का कुल भंडार चार साल के सबसे कम स्तर 676।33 लाख टन पर है। इसमें 266।45 लाख टन गेहूं और 409।88 लाख टन चावल शामिल है, जबकि एक अगस्त, 2021 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 564।80 लाख टन और चावल का स्टॉक 444।59 लाख टन था। पिछले साल की तुलना में जिन राज्यों में धान की रोपाई कम हुई है, उनमें झारखंड में 11।37 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 11।23 लाख हेक्टेयर, ओडिशा में 4।31 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 4।46 लाख हेक्टेयर, बिहार में चार लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 3।37 लाख हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 1।43 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना में 3।39 लाख हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 2।85 लाख हेक्टेयर कम है। ये सब चावल उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा आठ अन्य राज्यों में भी धान का क्षेत्रफल पिछले साल से कुछ कम है। कृषि उत्पादों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इनके निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस वर्ष उत्पादन घटने से निर्यात का प्रभावित होना स्वाभाविक है। पिछले साल लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था, लेकिन कुछ महीने पहले गेहूं के निर्यात पर सरकार को रोक लगानी पड़ी।

दुनिया के चावल बाजार में पिछले साल भारत की हिस्सेदारी 40 फीसदी के आसपास रही थी, पर इस बार उसमें भी कमी आने की आशंका बढ़ गयी है। जब सरकार इस साल के उत्पादन का अनुमान लगायेगी, तब इस बात की संभावना भी है कि चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। कृषि निर्यात में चीनी का भी बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 2021–22 के जो अनुमान प्रकाशित हुए हैं, उनमें बताया गया है कि गन्ना उत्पादन 43।1 करोड़ टन रहा है। गन्ने की खेती पर मानसून और अन्य कारकों का क्या असर पड़ता है, वह देखना होगा।

कृषि उत्पादन से संबंधित एक चिंता खाद्य मुद्रास्फीति की भी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट आयी है, जिसका फायदा हमें भी मिला है। सब्जियों में राहत नहीं मिल सकी है, पर दालों की कीमतों में कुछ कमी आयी थी, लेकिन फिर दालों के दाम बढ़ने लगे हैं। चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार, पिछले साल 2।76 करोड़ टन दलहन तथा 3।77 करोड़ टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। आलू–प्याज के भाव गिरने से भी महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। लेकिन अगर खरीफ उत्पादन में कमी आती है, तो मुद्रास्फीति का दबाव फिर से बढ़ने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, इस मामले में हमें किसी चमत्कार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मानसून का जो अस्थिर रवैया रहा है, उसका असर बाकी चीजों पर भी होगा। जैसी स्थितियां हैं और आगे का जो आकलन है, उसे देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान की वशद्धि से गेहूं की पैदावार कम रही है। कई जगहों पर तो यह असर 20 फीसदी तक रहा है। इसी कारण गेहूं से संबंधित सरकार के आकलन को स्वीकार कर पाना मुश्किल है। ऐसे में किसान पहले से ही नुकसान में है और अब खरीफ के मामले में भी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। मानसून की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों से सबसे अधिक नुकसान किसान को ही होता है। इसका सही आकलन तभी हो सकेगा, जब खरीफ की फसल बाजार में आयेगी। बीते साल कपास और सोयाबीन के अच्छे दाम किसानों को मिले हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक है। सरसों के भी अच्छे दाम मिले थे। अब देखना यह है कि उत्पादन में क्या कमी आती है और बाजार का रुख कैसा रहता है। उल्लेखनीय है कि कीमतों का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, लेकिन फसल खराब होने, बारिश न होने जैसे कारकों का पूरा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए सरकारें किसानों को सलाह देती थीं कि वे कब रोपाई करें या क्या वैकल्पिक फसल लगाएं, पर इस बार यह नहीं हो रहा है। जिन इलाकों में किसानों की फसल बर्बाद हुई है, वहां मुआवजा देने के बारे में सोचा जाना चाहिए। पिछले वर्षों में यह भी होता रहा है कि बारिश कम होने की स्थिति में किसानों को डीजल पर अनुदान दिया गया और बिजली आपूर्ति बढ़ायी गयी। इस तरह के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से बहुत से काम राज्य सरकारें अपने स्तर से भी कर सकती हैं।

प्रशिक्षक भर्ती नियमों में सुधार कब तक

पिछले दो वर्षों से सुन रहे हैं प्रशिक्षक कैडर के भर्ती व पदोन्नति नियमों में सुधार कर लिया है पिछले दो वर्षों से सुन रहे हैं प्रशिक्षक कैडर के भर्ती व पदोन्नति नियमों में सुधार कर लिया है, मगर अभी तक जूनियर प्रशिक्षक का स्केल और काम जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी का लिया जा रहा है। इससे अधिक अन्याय प्रशिक्षकों के साथ और अब क्या हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी करोड़ों लोगों में स्वयं व अपने देश को पदक जीत कर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है तो उस के पीछे जहां उस दृढ़ संकल्प, लगातार कठोर परिश्रम व अपनों की सहायता व दुआएं होती हैं, वहीं पर एक प्रशिक्षक की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अलग से राज्यों में खेल विभागों का गठन हुआ है। १९८२ के एशियाड के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का गठन किया। विभाग के गठन के चार दशक बाद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षकों के भर्ती व पदोन्नति नियमों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। हिमाचल प्रदेश के इस विभाग में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों, कनिष्ठ प्रशिक्षकों व युवा संयोजकों के पद सृजित हैं। इस विभाग का कार्य प्रदेश में युवा गतिविधियों व खेलों का विकास करना है। हिमाचल प्रदेश में यह विभाग खेल प्रशिक्षण, खेलों के लिए आधारभूत ढांचा व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता होने पर नगद पुरस्कार व अवार्ड देने के लिए बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के इस विभाग का निदेशक प्रशासनिक सेवा से ही अधिकतर नियुक्त होता रहा है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही आज तक दो बार ही विभागीय अधिकारी निदेशक पद तक पहुंच पाए हैं। उपनिदेशक और कभी कभी संयुक्त निदेशक पद तक विभाग के प्रशिक्षक व युवा संयोजक पदोन्नत होकर पहुंच जाते हैं। इन विभागीय अधिकारियों को अधिक तकनीकी जानकारी होती है। आजकल हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के पास कोई भी उपनिदेशक नहीं है। वरिष्ठ जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को उप निदेशक के पद पर बिठा कर काम चलाया जा रहा है। नियमित जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी भी केवल चार ही जिलों में हैं। राज्य के शेष जिलों में काम चलाऊ अधिकारी बिठा रखे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही उपनिदेशक के पद पर नियमित पदोन्नति की जाए तथा जिलों में भी नियमित अधिकारी हों। इस समय जो प्रशिक्षक जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद पर तदर्थ कार्य कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त नियमों में छूट देकर नियमित अधिकारी बना दिया जाए । इस विषय पर पहले भी इस कॉलम के माध्यम से लिखा जा चुका है, मगर लगता है कि सरकार के लिए युवा शक्ति व खेल प्राथमिकता पर नहीं हैं। विभाग में नाम मात्र के प्रशिक्षक हैं। अधिकतर खेलों में तो एक भी प्रशिक्षक पूरे जिले के लिए उपलब्ध नहीं है। विभाग में जो प्रशिक्षक नियुक्त हैं उन्हें कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। उसके बाद वे सेवानिवृत्ति तक भी प्रशिक्षक नहीं बन पाए हैं। विभाग में नियुक्त प्रशिक्षकों को जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए केवल २५ प्रतिशत ही कोटा है। ५० प्रतिशत युवा संयोजक व २५ प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।

योगीराज में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद शर्मनाक

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला करते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा राज में जनता के पैसों की खुलकर बर्बादी हो रही है। भ्रष्टाचार को खुली छूट मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने खुद तो जनता के हित में कुछ किया नहीं, समाजवादी सरकार में जो अच्छे काम हुए थे उन्हें बर्बाद करने को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद शर्मनाक है। खुद उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग में पिछले पांच वर्षों से चल रही अव्यवस्थाओं पर शर्मिंदा होते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में कहीं ठेले पर मरीज जा रहे हैं तो कहीं सड़क पर टेम्पों में प्रसव हो रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली तो कन्नौज में 100 बेड के अस्पताल में गर्भवती को इलाज नहीं मिला। पहले उसे 50 किलोमीटर दूर अस्पताल रेफर किया गया, वहां से भी भगाया गया तो टेम्पो में बच्चे का जन्म हुआ। गोरखपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला अस्पताल को वसूली का अड्डा बना दिया है। आपरेशन थियेटर से निकलने के बाद मरीज के परिजनों से स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा रूपए मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी सरकार में प्रसूताओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 102 और सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई थी जिसे भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला अपराध रोकने के लिए 1090 तथा अपराध नियंत्रण के लिए डायल 100 विश्वस्तरीय सेवा दी गई थी जिसे भाजपा सरकार ने 112 करके बरबाद कर दिया है।

चुनाव आयोग पर अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी चौनल के इंटरव्यू में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की बेईमानी से उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में हम हारे हैं। अखिलेश ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हुए बदलाव के बाद 2024 में होने वाले चुनाव में नया राजनीतिक विकल्प तैयार होगा। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन इसी साल होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। सपा प्रमुख ने कहा, देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है।

बलात्कार के आरोपियों को मड़ियांव और गोमती नगर विस्तार पुलिस ने पकड़ा

लखनऊ। लखनऊ कमिश्नरेट की मड़ियाव और गोमती नगर विस्तार पुलिस ने बलात्कार के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचा दिया है। मड़ियाव पुलिस के द्वारा अजीज नगर मड़ियांव के रहने वाले राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किए गए राजकुमार के खिलाफ 2 दिन पहले नाबालिग पीड़िता की मां ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया राजकुमार चौकीदार है। इसके अलावा गोमती नगर विस्तार पुलिस ने सफेद बारादरी के पास कैंसर बाग में रहने वाले प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया है । गोमती नगर विस्तार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया प्रमोद कुमार मूल रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला है प्रमोद पर आरोप है कि उसने एक महिला को शादी का झांसा देकर न सिर्फ उससे बलात्कार किया बल्कि उसे लगातार डराया धमकाया भी था।

जांच ऐजेसियों पर सवाल उठाना ठीक नही मनीष और मुख्तार के यहां रेड पर केशव मौर्य बोले

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। मनीष सिसोदिया के घर पर आज सीबीआई रेड को लेकर राजनीति गर्माने लगी है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया और यूपी में मुख्तार अंसारी के यहां ईडी के छापों को लेकर सवाल उठने लगे है। विपक्षी दल सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगा रहें है। इन आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि विपक्षी अगर सही है, तो डरें नही जांच में सहयोग करें।

आज लखनऊ में केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ,सपा और आप के नेता अगर सही हैं। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नही किया है तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच एजेंसियों पर सवाल नही उठाना चाहिए। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड पड़ने को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इसका ईडीसद शराब नीति की जांच नहीं है, ईडीसद अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना है। नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आया है। वह बीजेपी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से परेशान है। अमेरिका का अखबार तक सिसोदिया की सराहना करता है। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना है बल्कि वह विपक्ष को परेशान करना चाहते हैं। सीबीआई की कारवाई बीजेपी की हताशा, निराशा और बौखलाहट का नतीजा है। गुरुवार से ही मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का छापा चल रहा है। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई गुरुवार को छापेमारी देर रात तक चली। सांसद भाई अफजाल अंसारी के घर से तो ईडी की टीम देर शाम वापस चली गई, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रात 11 बजे तक ईडी की टीमें जांच करती रही।

उत्तर प्रदेश में जंगलराज, विकास का ढोल सिर्फ एक छलावा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 'जंगलराज' है और विकास का ढोल सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने ट्वीट किया, "बांदा जिले में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल के वर्षों से अधूरे पड़े रहने के कारण नाव हादसे में कई लोगों की मौत, हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या और अब हमीरपुर में सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज है तथा विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र है। मायावती ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून–व्यवस्था का सबूत है। इनका विकास भी कुछ खास जिलों तक सीमित है, जबकि प्रदेश के हर क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे।" गौरतलब है कि बांदा जिले के समगरा गांव में 11 अगस्त को एक नाव पलटने से उस पर सवार 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 16 अगस्त को हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर हरियाणा के हिस्ट्रीशीटर की तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया था।

जन्माष्टमी पर राज्यपाल आनंदीबेन व सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं

लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास से परिपूर्ण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का मानव जीवन में युगों–युगों से विशेष महत्व रहा है। भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का संदेश दिया है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यह पर्व देश और समाज में सौहार्द, भाईचारे एवं एकता को और मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना एवं अधर्म, अन्याय तथा अत्याचार समाप्त करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का जो संदेश दिया, उसकी प्रासंगिकता शाश्वत है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी सावधानियां बरतते हुए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाने की अपील की है।

रंगदारी मांगने वाला बदमाश को गुडम्बा में गिरफ्तार

लखनऊ। करीब 2 माह पूर्व गुडंबा थाना क्षेत्र में बने स्कॉर्पियो क्लब के संचालकों को डरा धमका कर अवैध वसूली मांगे जाने के मुकदमे में वांछित चल रहे प्रीति नगर अन्ना मार्केट मड़ियाव के रहने वाले सुभाष निषाद को आज गुडंबा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है ।

गिरफ्तार किए गए सुभाष निषाद के 3 साथी रामप्रकाश, रंजीत कुमार व सुरेश यादव को स्कॉर्पियो क्लब के संचालकों से अवैध वसूली मांगे जाने के मामले में पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।अवैध वसूली मांगे जाने के मुकदमे में सुभाष निषाद फरार चल रहा था जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया सुभाष निषाद अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से रंगदारी मांगने के साथ–साथ चंदा भी वसूल था।

विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी से जनता के धन के अपव्यय के साथ जनहित भी प्रभावित होता है। ऐसे में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के लिए तय नियमों के अनुरूप धनराशि का आवंटन किया जाता रहे। अनावश्यक विलम्ब करने की प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर मण्डलवार विभिन्न विकास परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनहित की विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सचेत किया कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। किसी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार अथवा अनावश्यक लेटलतीफी की सूचना मिलने पर सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव,सचिव स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी 18 मण्डलों में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर विस्तश्त रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त को विगत 05 माह में विभागों को जारी परियोजनावार बजट पर अब तक हुए व्यय का विवरण तथा अवशेष राशि के सम्बन्ध में विस्तश्त आख्या तैयार करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह परियोजनावार कार्यों की पुनः समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन का कोई अभाव नहीं है। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने विकास परियोजनाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था के चयन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवश्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। परियोजना की महत्ता के अनुरूप केन्द्र की कार्यदायी संस्थाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने शुचिता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विकास परियोजनाओं के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने वाली संस्था, परियोजना के क्रियान्वयन,निर्माण आदि की टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग न करें। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि युवाओं को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार अनेक विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। इसके तहत राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ जैसी निर्माणाधीन परियोजनाएं प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी। यह प्रोजेक्ट शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसलिए इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य की सतत निगरानी की जाए। कतिपय परियोजनाओं के बजट पुनरीक्षण की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि किसी भी परियोजना का बजट रिवाइज नहीं किया जाए। परियोजना शुरू करने से पहले सभी बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लिये जाएं।

खाटू श्याम मंदिर में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। श्री श्याम परिवार,लखनऊ द्वारा श्री श्याम मंदिर,बीरबल साहनी मार्ग, गोमती तट ,लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई। मंदिर परिसर में भव्य व आकर्षक पंडाल तैयार किया गया। जिसमे भजन संध्या का आयोजन हुआ। कान्हा के जन्मोत्सव पर श्याम प्रभु का मनमोहक श्रृंगार किया गया। श्याम प्रभु को सुन्दर वस्त्र पहनाया गया। शाम से ही शुभम गुप्ता, पवन मिश्रा व सुश्री गुडिया मिश्रा द्वारा मीठे–मीठे भजन प्रस्तुत किये गये। पवन मिश्रा ने जब राधे राधे जपो चले आयेंगे बिहारीकृ, भजन सुनाया तो माहोल कान्हा की भक्ति के रंग गया। अगले क्रम मे सुश्री गुडिया मिश्रा ने श्याम बरसाने आ जइयो बुला रही राधा प्यारीकृ, सुनाया तो पंडाल बाबा के जयकारों से गूंज उठा। मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे घंटा,घडियाल, शंख ध्वनि व भक्तों के जयकार के उद्घोष के बीच ष्नंद के आनंद भयो,जय कन्हैया लाल कीष्जन के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भक्ति के साथ भक्तों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया, मंदिर परिसर में भक्तों के लिए स्वादिष्ट व लजीज व्यंजन के स्टाल के साथ–साथ सेल्फी प्वाइंट्स भी बनाये गये है। जहाँ भक्तगण अपनी सेल्फी लेकर जन्माष्टमी के आयोजन की यादों को अपने कैमरे में संजोकर रख सकते हैं। भगवान के जन्मोत्सव के पश्चात पाँच पूज्य ब्राह्मण गण द्वारा स्वास्तिवाचन और पुरूषुक्त के मंत्रो के साथ लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया गया। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरण के साथ आयोजन का समापन हुआ।

कोरोना के 187 नए मरीज, आलमबाग में ही 45 मामले

लखनऊ। कोरोना संक्रमण में ठहराव या कमी नहीं दिख रही है। शुक्रवार को शहर में 187 लोग पॉजिटिव मिले तो गुरुवार को 147 लोग संक्रमित मिले थे। दो दिन में 334 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले 22 जून को 191 मामले सामने आए थे। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अफसर नए सिरे से संक्रमण पर काबू पाने का खाका बनाने में जुट गए हैं।

शुक्रवार को आलमबाग में सबसे ज्यादा 45 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है तो अलीगंज में 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चिनहट में 23 और सरोजनीनगर में 21 लोग वायरस की जद में आए हैं। इंदिरानगर में 19, कैसरबाग में 14 और एनके रोड इलाके में सात लोग पॉजिटिव हैं। रेडक्रास में छह, सिलवर जुबली में पांच, माल और टुड़ियागंज में तीन–तीन लोगों में वायरस मिला है। गोसाईंगंज में दो और मलिहाबाद में एक लोग संक्रमित मिले हैं।

केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना चाहती है मोदी सरकार

लखनऊ। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी पर आप यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है जिसे भाजपा हर हाल में रोकना चाहती है । दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है। अमेरिकी अखबार जो मोदी सरकार के बारे में छापता था कि कोरोना के टाइम पर लाखों की मृत्यु हुई,वही अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मोदी को देश के साथ खुश होना चाहिए, वो उल्टा मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड करवा रहे हैं। अगर देश में ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्यश पर काम न करने दें तो वो देश को क्या आगे लेकर जाएंगे। मोदी छोटी सोच से बाहर आइए अब केजरीवाल रुकने वाले नहीं हैं। संजय सिंह ने शराब नीति मुद्दा पर कहा कि गुजरात में भाजपा नेताओं द्वारा जहरीली शराब बनाई गई जिसके पीने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई ,क्या इनके खिलाफ सीबीआई जांच हुई? उन्होंने कहा कि केजरीवाल के गुजरात पहुंचते ही मोदी ष्की की रेवड़ीष् बोलकर हमलावर होते हैं जब केजरीवाल देश को बताते हैं कि मोदी ने दोस्तों को लाखों करोड़ों की फ्री की रेवड़ी दी तो ये सीबीआई– इडी लगा देते हैं। देशभर से लोग उनके भारत को नम्बर वन राष्ट्र बनाने के मिशन से जुड़ रहे हैं इसीलिए मोदी को रात भर एक ही चिंता रहती है कैसे केजरीवाल को रोका जाए?मोदी सरकार केजरीवाल से घबरा गई है सीबीआई से छापेमारी कराकर साफ हो गया कि 2024 का चुनाव भाजपा बनाम आप के बीच होगा।

पूर्व पीएम राजीव गांधी का जयंती आज मनायेगी कांग्रेस

लखनऊ। कांग्रेस शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनके कामों को जनता के बीच लेकर जाएगी और इस मौके पर ब्लाक, ग्राम सभा व जनपद स्तर पर झांकी, कवि सम्मेलन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। स्व. राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को है। मीडिया व कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम उनकी जंयती पर कांग्रेस और हमारे नेताओं के योगदान और बलिदान को लोगों को बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्व. राजीव गांधी युगदृष्ठा थे। प्रधानमंत्री के रूप में कम समय काम करने का मौका मिला लेकिन उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक काम आज भी देश के विकास की प्रेरणा हैं। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी के समय में ही पूरे देश में 600 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई। मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का ऐतिहासिक कानून बनाया। दूरसंचार क्रांति के माध्यम से मोबाइल और कम्प्यूटर घर–घर पहुंचाने का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। दल–बदल कानून लाकर देश के लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत किया और पंचायती राज अधिनियम से गांवों के लोकतंत्र को सशक्त बनाया और पंचायतों को न्यायिक अधिकार के साथ 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की।

विंड एनर्जी एवं हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में कनाडा तकनीकी का फायदा मिलेगा

प्रयाग दर्पण संवाददाता

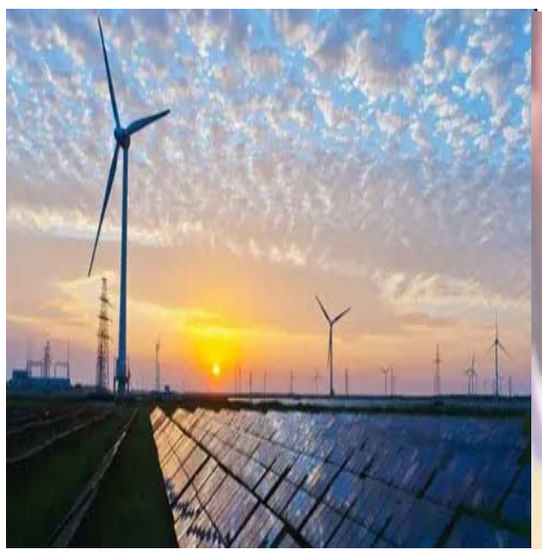

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. क.शर्मा से आज उनके सरकारी आवास 14 कालिदास मार्ग पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त मिस्टर कैमरुन मैके के नेतश्त्व में कनाडियन शिष्टमंडल ने मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री से प्रदेश के नगरीय निकायों में पानी की आपूर्ति, साफ–सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट, नगरी यातायात, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, विंड एवं ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी तथा लखनऊ की साफ सफाई, व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा की गई।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कनाडा के उच्चायुक्त ने लखनऊ की साफ–सफाई और सुव्यवस्था की प्रशंसा की। प्रदेश में नगर विकास के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई। शहरों की साफ सफाई एवं स्वच्छ रखने के लिए सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक की जा रही सफाई व्यवस्था, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले चौराहों, बाजारों आदि स्थानों पर दो से तीन बार की सफाई, सफाई में मशीनों के प्रयोग, शहरों के सुंदरीकरण के लिए वनरेबल पॉइंट का उपयोग कर पार्क उद्यान व सरोवर बनाने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आदि सभी कार्यों में निजी कंपनियों के सहयोग से किए जा रहे कार्यो, सामुदायिक शौचालयों की देखरेख, पार्कों उद्यानों सरोवरों के निर्माण में जनभागीदारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने आदि विषयों पर चर्चा की गई। श्री शर्मा ने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कनाडा पेट्रोलियम एवं गैस के क्षेत्र में एक समश्द्ध देश रहा है, फिर भी कनाडा में अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। खासतौर से विंड एनर्जी एवं हाइड्रो एनर्जी पर काफी अच्छा कार्य हुआ है। इस क्षेत्र में उनकी तकनीकी जानकारी का फायदा उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में मिलेगा। उन्होंने कहा कि कनाडिया शिष्टमंडल के प्रदेश में आगामी दौरे पर गांव का भ्रमण कराने को कहा, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें बताया कि मा0 प्रधानमंत्री जी के साथ कनाडा में तीन बार जा चुका हूं और वहां मेरे कई कनाडियन दोस्त हैं, जिससे उन्होंने मुलाकात करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कनाडियन शिष्टमंडल से मुलाकात काफी सकारात्मक रही।

उन्होंने नगरीय निकायो के विकास में एवं प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान कनाडा के उच्चायुक्त मि0 मैके ने लखनऊ शहर की साफ–सफाई को देख कर कहा कि पहली बार लखनऊ ऐसा साफ सुथरा शहर दिख रहा है और जहां तक मेरा मानना है कि लखनऊ शहर भारत के सर्वाधिक साफ–सुथरे शहरों में से एक है। लखनऊ शहर को साफ–सुथरा, व्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए उन्होंने नगर विकास मंत्री की प्रशंसा की और उन्हें इस कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बधाई दी है।

इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया

लखनऊ। राजधानी के चारबाग, बांसमंडी स्थित पुराने इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। खास बात यह कि इस मंदिर में प्रभु का जन्म नहीं करवाया जाता बल्कि जन्मदिन मनाया जाता है। श्री श्रीगौर राधाकृष्ण मंदिर की वरिष्ठ सदस्या तथा कार्यक्रम संयोजिका प्रीति गर्ग ने बताया कि में कई दिनों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। पूरे मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। सुबह 4.30 बजे भगवान का श्रंगार शुरू हुआ। अभिषेक के बाद फूलों का श्रंगार, वस्त्र, आभूषण धारण करवाने के पश्चात खीर का भोग लगा और मंगल आरती की गई। इसके बाद 9 बजे मंदिर के पट खुले तथा प्रभु जी का दर्शन लाभ पूरे दिन भक्तों को प्राप्त होता रहा। सुबह 9 बजे भोग व आरती के बाद अखण्ड कीर्तन शुरू हुआ जो रात 12.30 बजे तक चलता रहा। सांयकाल 4.30 भगवान को फलों का भोग लगाकर आरती की गई। शाम को 6.30 बजे तुलसी आरती के बाद 7 बजे भव्य आरती की गई।

अयोध्या में फिर टूटेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड,राम नगरी में छठे दीपोत्सव पर जलेंगे 14.50 लाख दिए

प्रयाग दर्पण संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर को इस बार राम नगरी में 14 लाख 50 हजार दीप जलाए जाएंगे। यानी इस बार भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2021 में 9,41,551 दीप राम की पैड़ी में प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। जिसे महा शिवरात्रि पर धर्म नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर 11 लाख 71 हजार 78 दीप जलाकर तोड़ा गया था। राम नगरी में इस बार रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 14.50 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए अधिकारिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम दीपोत्सव का आयोजन 51 हजार दीए के साथ हुआ था। 2018 में 3,01152 दीप जलाए गए। 2019 में इस दीपोत्सव कार्यक्रम को प्रांतीय स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके बाद 2019 में 5,50,000 मिट्टी के दीयों से रोशन कर दीपोत्सव मनाया गया

था। वहीं 2020 में 6,06,569 दीयों को सरयू के तट पर जलाया गया था। अब एक बार फिर साल 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए दीपोत्सव में 14 लाख 50 हजार दीप जलाने की तैयारी शुरू कर दिया है। छठे दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में अन्य वर्षो की तुलना में बहुत ज्यादा भीड़ होगा, क्योंकि वर्तमान में कोविड का असर नही है। सभी निर्माण कार्य को 30 सितम्बर 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। मंडलायुक्त ने आगे बताया कि जिलाधिकारी नितीश कुमार, नगर आयुक्त विशाल सिंह के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के साथ मेला के नोडल अधिकारी, विभाग के प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन के साथ बैठक हो चुकी है तथा जिलाधिकारी द्वारा भी इस माह के प्रथम सप्ताह में आवश्यक बैठकें की जा चुकी हैं। विभागों से कार्य योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया जा चुका है। अयोध्या में छठवां दीपोत्सव 23 अक्टूबर 2022 को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस बार 14 लाख 50 हजार दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने देते हुए बताया कि 30 सितंबर से पहले सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। डॉ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी समय से टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसमें एडीएम सिटी मेलाधिकारी को समय से समन्वय करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन, संस्कृति, सूचना, परिवहन, उद्यान, वन, ऊर्जा, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, राजकीय निर्माण निगम, विकास विभाग, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विवि, सिंचाई, जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, पंचायत, स्वास्थ्य, राजकीय राजमार्ग, प्राधिकरण, रेलवे, शिक्षा, हवाई पट्टी के संबंध में बिन्दुवार कार्य योजना प्रस्तुत हुई।

गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने पांच हजार जुर्माना ठोका

बहराइच। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट के जज मनोज कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी के जुर्म कबूल करने पर पूर्व में जेल में बिताई अवधि के अलावा पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। यह जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर त्वरित निस्तारण की दिशा में पहल है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट श्रीनिवास तिवारी व सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली के श्यामपुर नदौना निवासी सक्रिय बदमाश जोधी पासी पर विगत वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी जिला कारागार में एक वर्ष चार माह निरुद्ध रह चुका है।

चार्जशीट दाखिल होने पर केस का विचारण शुरू हुआ। कोर्ट में गुरुवार को पेश हुए आरोपी जोधी पासी ने जुर्म कबूल कर लिया। जिस पर उसे जज ने जिला कारागार में बिताई गई अवधि व पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषसिद्ध अपराधी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मंत्री दिनेश सिंह और बलदेव सिंह औलख ने की समीक्षा

प्रयाग दर्पण संवाददाता

गोण्डा। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और बलदेव सिंह औलख गोंडा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। विकास भवन में मंडल के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद गौ–आश्रय स्थल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। दोनों मंत्रियों ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अनुसूचित भाजपा पदाधिकारी के यहां पहुंचे। जहां सड़क खराब मिलने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई और गोंडा के विकास के लिए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद से बात की। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गोंडा के विकास के लिए जिन मंत्रियों से जरूरत होगी मैं उसके लिए निवेदन करूंगा। जो भी कमियां मिली है, उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। सरकार की मंशा है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप

काम किया जाए। इसी के लिए आज पूरे यूपी में हमारे मंत्री जिले में हैं और हम दोनों लोग गोंडा में हैं। विकास कार्यों की समीक्षा और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। 37 साल बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा जताया है। जनता की भरोसा के अनुसार जिले में काम हो रहा है। इसी को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यूपी के सभी मंत्री अलग–अलग जिलों में हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर निरीक्षण कर रहे हैं।

संक्षिप्त खबरे

किशोरी खटिक हत्याकांड में एक की जमानत खारिज

बहराइच। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट के जज राकेश कुमार पंचम ने किशोरी खटिक की हत्या व मवेशियों को गायब करने के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह वारदात जनवरी के दूसरे सप्ताह में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि रुपईडीहा थाने के निधिनगर संकल्पा में रिश्तेदारी में रह रहा किशोरी खटिक नौ जनवरी को मवेशियों को चराने जंगल के किनारे गया था। कुछ दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली थी। इस मामले में छत्रपाल ने तीन को नामजद कर केस दर्ज कराया था। इस मामले में निधिनगर संकल्पा निवासी आदिल उर्फ रूपई पुत्र कादिर खां को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था।

आरोपी के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को जज ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार कश्यप के तर्कों को सुनकर जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जीवीएम में दही हांडी व नश्त्य संग मनी जन्माष्टमी

बस्ती। जीवीएम कान्वेन्ट स्कूल में गुरुवार को दही हांडी व नश्त्य संग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। स्कूली बच्चे राधा–कृष्ण, वासुदेव, देवकी आदि की वेषभूषा मे सजधज कर विद्यालय आए। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर स्कूल परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हुए। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह एवं प्रबंधक संतोष सिह ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे मे प्रेरणादायक बातें बताई। विद्यालय के छोटे–छोटे बच्चों ने गाय के बछड़े के साथ खूब आन्नद लिया। दही हांडी प्रतियोगिता मे प्रतिभाग करने वाले बच्चों में यर्थाथ, दिव्यांश समश्द्ध, अभिराज, प्रिशा, आश्वी, आयत, अक्षत, फातिमा सलीम, पीहू, शिफा, आशुतोष आदि शामिल रहे। राधा के वेषभूषा में मान्या, वनिका, नित्या, मरियम, प्रिशा शगुन आदि रहे। श्रीकृष्ण के वेषभूषा में शौर्य, वेद, शिवेंद्र , आशुतोष, हार्दिक, अभिराज व्याख्या और अर्थव मुख्य रहे। इस अवसर पर बब्बी प्रकाश, रूबीना, पूजा, ममता, पूर्णिमा, प्रियंका, मंजू, अनीता सहित अन्य शिक्षकों ने सहयोग प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बस्ती दौरा आज, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक

बस्ती। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बश्जेश पाठक 20 अगस्त को बस्ती आयेंगे। बस्ती की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को बताया कि पाठक 20 अगस्त को राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा जनपद अंबेडकर नगर से बस्ती आयेंगे।इस दौरान वह जिले में चल रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तत्पश्चात् जनपद के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह 02रू20 बजे से बस्ती से राज्य मुख्यालय लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

सरयू नदी में डूबे युवक का मिला शव, 30 घंटे से चल रही थी तलाश

बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के कटरिया–चांदपुर तटबंध से पैर फिसलने से सरयू नदी में लापता हुए युवक का बश्हस्पतिवार को 30 घंटे बाद शव मिला। घटनास्थल से करीब पांच किमी दूर टकटकवा गांव के पास नदी के किनारे उतराता हुआ शव ग्रामीणों ने देखा। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने शव की शिनाख्त की। दुबौलिया कस्बा निवासी राजकुमार चाट की दुकान लगाते थे। बुधवार सुबह घर से साइकिल लेकर शौच के लिए गए थे। कटरिया–चांदपुर तटबंध पर बाढ़ चौकी के पास बने ठोकर पर पैर फिसलने के कारण वह सरयू नदी में गिर गए। धारा तेज होने के कारण वह फौरन लापता हो गए। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन की गई, लेकिन राजकुमार का पता नहीं चल सका। घटना के दूसरे दिन बश्हस्पतिवार को करीब 30 घंटे बाद दुबौलिया थाना क्षेत्र के टकटकवा गांव के पास नदी किनारे ग्रामीणों ने एक शव देखा। हालांकि नदी में लापता युवक की तलाश में आजमगढ़ से पीएसी 20वीं बटालियन के छह गोताखोर एसओ दुबौलिया विनोद कुमार के साथ सर्च ऑपरेशन नदी में चला रहे थे।

साल भर से देखा जा रहा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण

बाराबंकी। जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र के रमपुरा तिलवारी गांव में लोग साल भर से तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। यहां आए दिन लोगों को तेंदुआ दिखता रहता है। जिसका ग्रामीण समय–समय पर वीडियो भी बनाते रहते हैं। इन दिनों भी एक वीडियो यहां से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव के बाहर तेंदुआ सोता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना पर वन विभाग की टीम क्षेत्र में आकर खानापूर्ति कर वापस लौट जाती है। वन विभाग की ढुलमुल रवैया से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। लोग अपने बच्चों और जानवरों की सुरक्षा के लिए परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहां साल भर से तेंदुआ देखा जा रहा है। लेकिन वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जो भी वन विभाग का अधिकारी आता है वह तेंदुएं के पग चिन्ह देख कर वापस चला जाता है। जिससे ग्रामीण तेंदुए की दहशत में जीने को मजबूर है।

एक साल से बंद है गौशाला, छुट्टा जानवरों का आतंक झेल रहे किसान

प्रयाग दर्पण संवाददाता

ckjkcdhA जिले में बंकी ब्लॉक की जरहरा गांव में गौशाला बंद होने से किसानों की समस्याएं बढ़ रही है। गौशाला बंद होने से छुट्टा जानवर क्षेत्र में किसानों के खेत की हरी–भरी फसल को चट कर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि साल भर पहले यहां पर गौशाला बनाई गई थी। गौशाला में जानवरों के रहने की समुचित व्यवस्था की गई थी। लेकिन साल भर से गौशाला बंद पड़ी है। गौशाला में कोई भी जानवर नहीं रखा जा रहा है। जिससे क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की भरमार है। यह सभी जानवर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे किसान काफी परेषान है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के जितने भी छुट्टा जानवर हैं उन्हें पकड़कर इस गौशाला में रखा जाए ताकि किसानों की फसल बच

सकें। नवाबगंज तहसील क्षेत्र के बंकी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जरहरा गांव में छुट्टा जानवरों को रखने के लिए सालों पहले गौषाला बनवाई गई थी। जिस समय यह गौषाला बन कर तैयार हुई उस समय इसमें जानवर रखे गए थे। लेकिन साल भर पहले से यहां से सभी जानवर को हटा दिया गया। तब से यह गौषाला बंद पड़ी है। गौषाला बंद होने के चलते क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की भरमार है। यह सभी छुट्टा जानवर झुंड बनाकर किसान की फसलों को खत्म कर दे रहे हैं। रात में यह सभी जानवर चौराहा और सड़क पर झुंड बनाकर बैठे रहते हैं। गाड़ियां आने के बाद भी यह रोड से नहीं हटते। जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं।

जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू

ckjkcdhA जिला चिकित्सालय बाराबंकी में डायलिसिस यूनिट का गुरुवार को षुभारंभ हुआ। राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद विभाग सतीष चन्द्र षर्मा और सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान संतोश नाम के एक मरीज का डायलिसिस किया गया। राज्यमंत्री ने तैनात चिकित्सकों को डायलिसिस से सम्बन्धित आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। कहा कि जनपद के किडनी मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे जनपद नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें उत्तम व सुव्यवस्थित प्रबंध के साथ डायलिसिस सुविधा मुहैया होगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, विधायक दिनेष रावत, विधान परिशद सदस्य अंगद कुमार सिंह, जिलाधिकारी डॉ. आदर्ष सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामजी वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेष कुमार मौजूद रहे।

शासन को भेजी गई खरीफ फसलों की हानि की सर्वे रिपोर्ट

बस्ती। जिला प्रशासन ने खरीफ फसल के संभावित नुकसान का आंकलन कृषि, सिंचाई व राजस्व विभाग से कराकर सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। अब क्षेत्रवार फसल नुकसान की विस्तृत आख्या तैयार करने में आपदा प्रबंधन विभाग को लगाया गया है। जिले में अभी तक होने वाली औसत बरसात का मानक भी पूरा नहीं हो सका है। अभी तक मात्र 30 फीसदी बारिश हुई है जबकि सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए 44 फीसदी या इससे कम बरसात होने का मानक है। ऐसे में किसानों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार से जिले को सूखाग्रस्त जनपद घोषित कराने की मांग की है। जिला कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कितनी बरसात हुई इसका आंकड़ा प्रतिमाह शासन को भेजा जाता है। इसके आधार पर ही सरकार के स्तर पर मिलने वाली मदद का निर्धारण होता है। फिलहाल अगस्त माह चल रहा है। उम्मीद है कि बरसात का औसत बढ़ने से किसानों को राहत मिल सके। बताया कि जिले में बुवाई की गई फसलों के लिए अब तक सात सौ मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। उसके सापेक्ष पूरे जिले में मात्र 2.09 फीसद ही बारिश हुई है। यह औसत बरसात का तीस प्रतिशत भी नहीं है। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा जिला प्रशासन ने जिले में हुई वर्षा को आधार बनाते हुए आंकलन रिपोर्ट का प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेज दिया है। फसलों के नुकसान पर क्षेत्रवार विस्तृत आख्या तैयार कराने के लिए निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग के दे दिया गया है। सूखाग्रस्त जिला होने के कई मानक होते हैं। जिसमें बारिश कम होने के साथ क्षेत्र में रकबे के आधार पर कितनी फसल बोयी गई इसके प्रतिशत का भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। इसीलिए विस्तृत आख्या जरूरी है।

दहेज उत्पीड़न के चार मामलों में 23 ससुराली नामजद

बस्ती। दहेज के लिए विवाहिता के उत्पीड़न के अलग–अलग चार मामलों में पुलिस ने 23 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया है। महिला थाना, पैकोलिया, सोनहा थाने में यह चारों मामले दर्ज हुए हैं। महिला थाना में तहरीर देकर रीना देवी ने बताया है कि उनकी शादी नगर थाना क्षेत्र के जोगीपुर निवासी गंगाराम के साथ हुई है। आरोप है कि ससुराल में बाइक की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गई। महिला थाने में पति गंगाराम के अलावा ससुर रामजीत, सास फूलमती समेत आठ पर केस दर्ज किया गया है। महिला थाने में ही तहरीर देकर वाल्टरगंज क्षेत्र की रागिनी सोनी ने बताया कि संतकबीरनगर कोतवाली के दलेलगंज निवासी सूरज वर्मा के साथ उनकी शादी हुई है। उनका आरोप है कि ससुराल में दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने पति के अलावा ससुर हरिश्चंद्र, सास मीरा वर्मा समेत चार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सोनहा पुलिस ने ससुराल में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में बलरामपुर जिले के गेड़सा थानांतर्गत अजगरी निवासी पति इरशाद, ससुर सज्जाद अली, सास सैयद्दा खातून समेत सात ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पैकोलिया पुलिस ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की तहरीर पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में गोंडा जनपद के मोतीगंज थानांतर्गत नगरा निवासी पति अमन सिंह, सास कामिनी सिंह, ससुर श्रीदत्त सिंह समेत चार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विजिलेंस टीम को ग्रामीणों ने घेरा,स्थानीय लोगों ने किया गाली-गलौज और अभद्रता

बाराबंकी। जिले में बढ़ रहे बिजली चोरी के मामलों को रोकने के लिए लगातार चौकिंग की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई बार बिजली कर्मचारियों के साथ गाली–गलौज और अभद्रता के मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। यहां सिरौलीगौसपुर विद्युत उपकेंद्र से गांव में एसडीओ व अन्य विद्युत कर्मचारियों के साथ विजिलेंस की टीम बिजली चोरी पकड़ने गई थी। टीम जब गांव में बिजली चोरी की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए। उग्र ग्रामीणों ने विद्युत टीम के साथ जमकर अभद्रता और गाली गलौज की। ग्रामीणों का उग्र रूप देख टीम वापस लौट आई। टीम ने ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस से शिकायत की है। पूरा मामला सिरौलीगौसपुर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के मेलारायगंज गांव का है। यहां एसडीओ व अन्य विद्युत कर्मचारियों के साथ विजिलेंस की टीम गांव में विद्युत चोरी की चेकिंग करने गई थी। टीम गांव

में विद्युत चोरी की चेकिंग करते हुए जब मॉर्निंग रेड पर बने घरों में चेकिंग करने पहुंची तो उस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए। उग्र हुए ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम सहित अन्य विद्युत कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और जमकर अभद्रता की। इकट्ठा हुए ग्रामीणों के द्वारा की जा रही अभद्रता को देखते हुए टीम वहां से लौटकर गांव के बाहर आ गई। गांव के बाहर से टीम ने स्थानीय बदोसराय कोतवाली को इस घटना के बारे में जानकारी दी। विद्युत टीम के साथ अभद्रता की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। विद्युत कर्मचारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दिया है।

घर में घुसकर रेप मामले में जमानत याचिका खारिज

बहराइच। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट के जज राकेश कुमार पंचम ने दलित युवती के साथ घर में घुसकर रेप, धमकी व गाली गलौज, दलित उत्पीड़न अधिनियम के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। वारदात 24 मई की रात में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि देहात कोतवाली के एक गांव में 24 मई की रात युवती घर पर अकेली थी। इसी दौरान हुजूरपुर थाने के पुरैनी गांव निवासी अभिषेक मिश्रा पुत्र प्रेम लाल ने घर में घुसकर युवती के साथ रेप की वारदात की थी। विरोध करने पर जाति सूचक गाली दी थी।

वारदात की वीडियो क्लिप भी बनाई थी। इस मामले में देहात कोतवाली में अभिषेक मिश्रा को नामजद कर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

संस्कृति का संरक्षण व उन्नयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध : दिनेश रावत

प्रयाग दर्पण संवाददाता

बाराबंकी। देश का भौतिक सामाजिक नैतिक आर्थिक विकास के साथ–साथ बोली, भाषा, कला और संस्कृति का संरक्षण व उन्नयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह विचार दिनेश रावत विधायक हैदरगढ़ ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज के सहयोग से गुलजार फाउण्डेशन द्वारा नगरपालिका परिषद सभागार में आयोजित दो दिवसीय भोजपुरी लोकरंग गीत महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। श्री रावत ने गुलजार फाउण्डेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय बोलियों के विकास से हिन्दी समृद्ध होती है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सभासद प्रतिनिधि आलोक वर्मा ने कहा कि भारतीयता का डंका विश्व मे बज चुका है। चाहे योग हो या आयुर्वेद। श्री वर्मा ने यह भी कहा कि भोजपुरी और अवधी बोलने वाले समझने वाले भारत से बाहर भी हैं। दूसरे दिवस प्रातः दीप जलाकर महोत्सव शुभारम्भ करते हुए ज्योति सिंह जिला पर्यटन

अधिकारी बाराबंकी ने कहा कि बोलियों और संस्कृतियों का विकास न सिर्फ इतिहास का संरक्षण है बल्कि इनमें रोजगार और कैरियर भी समाहित है स्वरोही डांस एवं म्यूजिक ग्रुप बाराबंकी द्वारा भोजपुरी गीतों की नृत्य पूर्ण प्रस्तुतियाँ खूब सराही गयीं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सारंग के संचालन में सम्पन्न महोत्सव में मनोरम चौरसिया, संतोष कुमारी, शिल्पा देवी, दीप माला, धर्मेंद विद्यार्थी, लता श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, शिवानी शुक्ला ने भी गीत प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। समारोह में कवि ओपी वर्मा ओम, अनिल श्रीवास्तव लल्लू, सदानन्द वर्मा, साहब नारायण शर्मा, डॉ मोहम्मद सुहैल, जैनुल आबेदीन डॉ मुनीर अहमद जावेद, संदीप श्रीवास्तव, इकबाल राही, प्रोमिला श्रीवास्तव,प्रीति शुक्ला, अब्दुल खालिक, अनिल शुक्ला,रमेश चन्द्र रावत, डॉ खदीजा, खंसा कैफ्श उपस्थित रहे।

जिला चिकित्सालय में पहली डायलिसिस यूनिट का सांसद व राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन

बाराबंकी। जिला चिकित्सालय बाराबंकी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन सतीश चन्द्र शर्मा राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं उपेन्द्र सिंह रावत सांसद बाराबंकी के संयुक्त कर कमलों द्वारा किया गया है। इस

अवसर पर संतोष नाम के एक मरीज का डायलिसिस किया गया। राज्यमंत्री ने तैनात चिकित्सकों को डायलिसिस से सम्बन्धित आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद के किडनी मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे जनपद नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें उत्तम व सुव्यवस्थित प्रबन्ध के साथ डायलिसिस सुविधा मुहैया होगी। इस कार्यक्रम में श्रीमती राजरानी रावत अध्यक्ष जिला पंचायत, दिनेश रावत विधायक, अंगद कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, जिलाधिकारी डॉ0 आदर्श सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 रामजी वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 बृजेश कुमार व बड़ी संख्या में चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी एवं देवाशीष चन्द्रा, स्टेट हेड, संदीप पाल, एस्काग संजीवनी व अन्य लोग सम्मिलित हुए।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक, प्रकाशक स्वतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य) द्वारा रमा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1–ए, बेली रोड, नया कटरा, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर, 1269/1073 मां श्री आश्रम, मालवीय नगर, बाबा जी का बाग, प्रयागराज से प्रकाशित।

–: संस्थापक :–

स्व0 श्रीकांत शुक्ल उर्फ स्वामी कांतेश्वरानंद भारती काली बाबा

संपादक

स्वतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य)

मोबाइल नंबर 9450475366

Email

prayagdarpan@gmail.com

R.N.I. NO.UPHIN/2014/59804

इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।